



गैर-सरकारी संगठनों के वदिशी अंशदान पर सख्ती

प्रलिमिंस के लयि:

गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), वदिशी अंशदान (वनियिमन) अधनियिम

मेन्स के लयि:

वदिशी अंशदान का दुरुपयोग और इसका नयितरण

चर्चा में क्यौं?

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 'वदिशी अंशदान (वनियिमन) अधनियिम' (Foreign Contribution Regulation Act -FCRA) के तहत 6 'गैर-सरकारी संस्थाओं' (Non-Governmental Organizations or NGOs) का लाइसेंस रद्द कर दया गया है।

प्रमुख बदि:

- वर्ष 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनि 6 NGOs के लाइसेंस रद्द कयि गए हैं उनमें से 4 ईसाई संगठन (Christian Associations) हैं।
- इनमें से कई संगठनों के दानकर्त्ताओं के प्रभाव के संदर्भ में चतिाएँ व्यक्त की गई थी।
- इससे पहले वर्ष 2016 में भी FCRA के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण लगभग [20,000 गैर-सरकारी संस्थाओं के लाइसेंस रद्द](#) कर दयि गए थे।
- ध्यातव्य है कि गैर-सरकारी संस्थाओं को वदिशी चंदा/अंशदान प्राप्त करने के लयि FCRA लाइसेंस प्राप्त करना अनविर्य होता है।
- वर्तमान में देश में 22,457 NGOs या अन्य संगठन FCRA के तहत पंजीकृत हैं, जबकि वर्ष 2012 से अब तक 20,674 NGOs का FCRA लाइसेंस रद्द कयि जा चुका है और 6,702 NGOs के FCRA लाइसेंस नवीनीकरण के अभाव में समाप्त को गए।

प्रभावति संस्थाएँ और पृष्ठभूमि:

- एकरथिसोकुलसि नॉर्थ वेस्टर्न गॉसनर इवैजेलिकल (Ecreosoculis North Western Gossner Evangelical)- झारखंड
- एवैजेलिकल चर्चेस एसोसिएशन (Evangelical Churches Association- ECA)- मणपुर (वर्ष 1952 में स्थापति, यह एक वेल्श प्रेस्बिटरियन मशिनरी से संबंधित है, जिसने 1910 में भारत का दौरा किया था।)
- नॉर्थवेस्टर्न इवैजेलिकल लूथरन चर्च (Northern Evangelical Lutheran Church)- झारखंड (वर्ष 1987 में स्थापति, यह लूथरन परंपरा पर आधारित विश्व के 99 देशों में फैले 148 चर्चों के समूह का हिस्सा है।)
- न्यू लाइफ फ़ैलोशिप एसोसिएशन (New Life Fellowship Association- NLFA)- मुंबई (वर्ष 1964 में न्यूजीलैंड के न्यू लाइफ चर्च से मशिनरियों के आगमन के बाद इस संस्था ने भारत में 1960 के दशक में कार्य करना प्रारंभ किया।)
 - गृह मंत्रालय द्वारा 'राजनंदगाँव लेप्रोसी हॉस्पिटल एंड क्लिनिक' (Rajnandgaon Leprosy Hospital and Clinics) और 'डॉन बॉस्को ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी' नामक दो अन्य NGOs के FCRA लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है।

FCRA लाइसेंस नरिस्तीकरण से जुड़े पूर्व मामले:

- वर्ष 2017 में गृह मंत्रालय द्वारा अमेरिका के 'कंपैशन इंटरनेशनल' (Compassion International) नामक NGO को धार्मिक मतांतरण को बढ़ावा देने से संबंधित गतिविधियों में शामिल पाए जाने के बाद संस्था को भारत में अपनी कार्यक्रमों को बंद करना पड़ा था।
- तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव के अनुसार, 'कंपैशन इंटरनेशनल' द्वारा FCRA के दिशा निर्देशों का सही से पालन नहीं किया जा रहा था।
- इसके अतिरिक्त वर्ष 2017 में ही 'ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रपीज़' (Bloomberg Philanthropies) नामक अमेरिकी धर्मार्थ संगठन से अनुदान प्राप्त करने वाले दो अन्य NGOs के FCRA लाइसेंस के नवीनीकरण के आवेदन को रद्द कर दिया गया था।
 - 'ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रपीज़' न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर और अरबपति माइकल ब्लूमबर्ग द्वारा स्थापित एक धर्मार्थ संस्थान है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री और न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने 'ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रपीज़' की सहायता से भारत में 'स्मार्ट सिटीज़' (Smart Cities) के निर्माण हेतु एक संयुक्त पहल की घोषणा की थी।

कारण:

- नवंबर 2019 में कुछ हद्दि समूहों ने NLFA पर धार्मिक मतांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था और इस संदर्भ में एक पुलिस शिकायत भी दायर की थी।
- गृह मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, 10 फरवरी 2020 को NLFA के FCRA लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था।

भारत में NGOs से जुड़ी समस्याएँ:

- वर्ष 2015 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दी गई जानकारी के अनुसार, भारत में सक्रिय कुल NGOs की संख्या लगभग 31 लाख बताई गई थी।
- देश में बढ़ी संख्या में NGOs के कार्यों और वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में पारदर्शिता का अभाव पाया गया है।
- वर्ष 2015 में देश में सक्रिय कुल NGOs में से 10% से भी कम ने ही अपनी बैलेंस शीट और आय-व्यय विवरण को जमा करने से संबंधी अनविद्यताओं को पूरा किया था।
- वर्ष 2017 में अनेक NGOs को लगातार 5 वर्षों तक अपने वार्षिक रिटर्न न दाखिल करने के कारण नोटिस जारी किया गया था।

गैर-सरकारी संस्था (Non-Governmental Organization or NGO):

- गैर-लाभकारी या गैर-सरकारी संस्थान या एनजीओ (NGO) से आशय ऐसी संस्थाओं से है जो न तो सरकार का हिस्सा होती हैं और न ही वे अन्य व्यावसायिक संस्थानों की तरह लाभ के उद्देश्य से कार्य करती हैं।
- भारत में 'धार्मिक वनियास अधिनियम, 1863', सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882' आदि के तहत NGOs का पंजीकरण किया जाता है।

वदिशी अंशदान:

- वदिशी अंशदान (वनिधिमन) अधिनियम, 2010 के तहत किसी व्यक्ति/संस्था/कंपनी आदि द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी वदिशी स्रोत से उपहार के रूप में प्राप्त कोई वस्तु, मुद्रा या प्रतभूतियों (जसिका मूल्य उस तिथि को 25,000 रुपए से अधिक हो) को वदिशी अंशदान के रूप में परिभाषित किया गया है।

'वदिशी अंशदान (वनिधिमन) अधिनियम'

(Foreign Contribution Regulation Act -FCRA):

- किसी वदिशी नागरिक या संस्था द्वारा भारत में किसी NGO या अन्य संस्थाओं को दिये गए अंशदान को वनिधिमति करने के लिये वर्ष

1976 में वदिशी अंशदान (वनिधिमन) अधनियिम लागू कयिा गया ।

- वर्ष 2010 में इस अधनियिम में बड़े पैमाने पर सुधार कयिे गए ।
- भारत में कार्यरत NGOs को वदिशी अंशदान प्राप्त करने के लयिे FCRA के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय में पंजीकरण कराना अनविर्य होता है ।
- इस अधनियिम के तहत NGOs का FCRA लाइसेंस पाँच वर्ष के लयिे वैध होता है ।
- FCRA के तहत पंजीकरण के बगैर कोई भी NGO या अन्य संस्थान 25,000 रुपए से अधिकि की आर्थकि सहायता या कोई अन्य वदिशी अंशदान नहीं स्वीकार कर सकते ।

आगे की राह :

- NGOs समाज में सरकार और नज्ी क्षेत्र की पहुँच से दूर रह गए लोगों तक मूलभूत सुवधिएँ पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं ।
- ऐसे में सरकार को यह भी सुनिश्चति करना चाहयिे कि किसी भी सामाजकि संस्था पर राजनीतिक दुर्भावना या कानूनों के दुरुपयोग के माध्यम से गलत कार्रवाई न की जाए ।
- हाल के वर्षों में देश में NGOs की कार्यशैली से संबंधति अनयिमतिताओं को देखते हुए देश में NGOs के पंजीकरण के नयिमों में आवश्यक सुधार कयिे जाने चाहयिे ।
- NGOs के अंशदान और वत्तीय व्यय के वविरण की नयिमति जाँच की जानी चाहयिे ।

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/govt-suspends-fcra-clearance-of-four-christian-groups>